

सम्पादकीय राहुल ने बताई वस्तुस्थिति

अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उसे लेकर कई मुद्दों पर फिर से बवाल हुआ है। टेक्सास के इलाक़ में मास्टीयों के बीच उन्होंने जो कहा था, उसे लेकर गिरिजा सिंह, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत तत्कालीन दो दर्जन मान्यताओं ने अपनी समझ और पार्टी लाइन के अनुसार राहुल की आलोचना कर दी है। अब वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब के सम्माने राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उसकी आलोचना एवं तोड़-मरोड़ करने योग्य अंश निकालकर मान्यता हमलावर तो है पर राहुल द्वारा व्यक्त विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत समी को है। अमेरिका किसी भी देश में लोकतंत्र के बन्ने-बिगड़ने को वैश्विक दृष्टिकोण से देखने का आदी है। राहुल ने इसी देश की अपनी पिछली यात्रा एक सांसद के रूप में की थी, तो इस बात वे वहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर हैं। इस पद की अहमियत को भी लोकतांत्रिक रूप से समझ और परिपक्व देश जानता है। पहले के मुक़ाबले मान्यता का अधिक तिलमिलाना स्वाभाविक तो है लेकिन राहुल देश की वास्तविकताओं से वहां की प्रेस को अवगत कर चुके हैं। हालांकि जिस मंच को उन्होंने सम्बोधित किया वह कोई स्थानीय प्रेस नहीं बल्कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वह अंतरराष्ट्रीय प्रेस विद्यार्थी है। जून, 2023 में भी वे इस मंच को सम्बोधित कर चुके थे। पहले तो यह बात कर ली जाये कि उनके किन बयानों को मान्यता अपने पक्ष में मोड़ रही है। आरक्षण को लेकर उन्होंने जो कहा है, उसका आशय यह था कि 'जब आरक्षण ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ें, तब उस पर सोचा जायेगा।' इसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि कांग्रेस आरक्षण ख़त्म करने के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने साफ़ किया कि कांग्रेस आरक्षण को 50 प्रतिशत तक घटाना चाहती है। पाकिस्तान को लेकर पूरे माये ख़याल पर उनकी लाइन वही थी जो कांग्रेस की सरकार के रहते थी। उन्होंने कहा कि उस देश से आतंकवादी गतिविधियां ख़त्म होनी हैं। यह सर्वविदित है और पहले से अमेरिका तक इसे कहना आया है। सरकार समर्थक मीडिया इसे मोदी के साथ राहुल का होना बतला रहा है। ऐसे ही, बांग्लादेश में हो रही हिंसा को भी उन्होंने ग़लत बताया है। बहुत सम्भव है कि मान्यता का आईटी सेल इसे ऐसा प्रस्तुत करे कि 'वहां के अल्पसंख्यकों (हिन्दू) के साथ हो रही हिंसा को लेकर राहुल को भी बयान देना पड़ा।' इन दोनों-तीनों बातों में दम नहीं है और बहुत मरोड़े के साथ कहा जा सकता है कि राहुल के कई बयानों को जिस प्रकार से पहले तोड़ा-मरोड़ा गया था लेकिन वे प्रयास कोई कारण नहीं हो पाये थे, उसी प्रकार यह दुष्प्रचार भी बहुत लम्बा टिकने वाला नहीं है। ऐसे एक-दो मुद्दों को छोड़ दिया जाये तो मान्यता के पास राहुल की आलोचना हेतु गिने-बुने हथियार ही रह जाते हैं। जैसे, उन्होंने बात के लिये कोसा जाये कि उन्होंने भारत की बदनामी विदेशी धरती पर की है, आदि राहुल के मापण के कंटेंट पर आये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र की वर्तमान हालत, उसके इस स्थिति तक पहुंचने और अविष्य की तस्वीर का ख़ाक़ खींचा है। विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनका दायित्व है, उन्होंने वह पूरा किया है। उन्होंने बतलाया कि 2014 में, यानी जब मान्यता ने केन्द्र की सरकार बनाई थी, तभी से सत्ता ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर ऐसा हमला करना शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस कठिनाई से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही, नरेन्द्र मोदी ने संसद के सारे सभ्य बन्द कर दिये हैं। आम तौर पर लोकतंत्र के लिये काम करने वाले सारे संस्थान बन्द कर दिये हैं।

मुस्लिम आबादी के केंद्रीयकरण की पॉकेट, मेवात के इलाके को केंद्रित कर, गोरक्षा के नाम पर खासतौर पर हिंसक गिरोहों को संगठित किया गया है, जिनकी गतिविधियों ने मेवात के इलाके को देश की माँब लिचिंग की राजधानी ही बना दिया है। इसी सिलसिले के हिस्से के तौर पर, पिछले ही साल फरवरी में कथित गोरक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गयी थी।

गोरक्षा के नाम पर, हरियाणा में फरीदाबाद में अठारह-उन्नीस साल के, बारहवीं कक्षा के छात्र, आर्यन मिश्र की हत्या की वारदात के बाद, अगर किसी को यह लग रहा हो कि कम से कम अब, गोरक्षा की आड़ में भीड़ हिंसा तथा भीड़ हत्याओं का सिलसिला थम जाएगा, तो अब उसकी यह ग़लतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ऐसा सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि जिस कार में आर्यन था उसका तीस किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए पीछा करने वाले और अंततः उसे नजदीक से गोली मारने वाले गिरोह के सरगना, अनिल कौशिक ने बाद में जब आर्यन के घरवालों के सामने अपनी "गलती" मानी और घटना पर पछतावा जताया, तो यह सिर्फ़ इसका पछतावा था कि मुसलमान के धोखे में, उनके हाथों से एक हिंदू ब्राह्मण लड़का मारा गया था। ऐसा सिर्फ़ इसलिए भी नहीं है कि पुलिस शुरूआत में सुलह-समझौते की कोशिश करते हुए, मुक्त के परिजनों को इसी पर कनिष्क करने में लगी हुई थी कि आर्यन की मौत एक "गलती" थी और यह गलती करने वाले "भले लोग" थे, जिनकी शराफत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वे खुद ही गलती होने की बात मान रहे थे। और ऐसा सिर्फ़ इसलिए भी नहीं है कि सत्ताधारी संघ-भाजपा द्वारा नियंत्रित मीडिया द्वारा अनदेखी के जरिए, इस भयावह त्रासदी को कानून व व्यवस्था का मामूली मामला बनाने की ही कोशिश नहीं की गयी है, इन पक्षियों के लिखे जाने तक न तो शासन के किसी प्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार की सुध लेने की जरूरत समझी थी और न ही सत्ताधारी संघ-भाजपा जोड़ी का कोई अदना नेता तक उनसे मिलने गया था। यहां तक कि पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की स्टडी घोषणा तक नहीं की गयी थी। इस हृदय विदारक कांड के किसी खास अंश को लेकर किसी ग़लतफहमी की गुंजाइश न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद को गोरक्षक बताने वाले इस तरह के गोंगुडों का असली सामाजिक-राजनीतिक-वैचारिक सहरा, कथित संघ परिवार इस जगह का स्पष्टीकरण जहां से आना चाहिए, इन पक्षियों को तज्ज्ञान नजर नहीं आता है। उल्टे स्वघोषित संघ परिवार के निर्विवाद संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के शीर्ष नेताओं से एक, इंद्रेश कुमार पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, माँब लिचिंग की भयावह घटनाओं को यह

हिंदुस्तान से लिचिंगिस्तान!

कहकर मामूली बनाते ही दिखाई दे रहे थे कि लिचिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए: 'न कोई ईसान की लिचिंग और न कोई गाय की लिचिंग!' इस तरह वह नरहत्या को गोहत्या में बराबरी ही स्थापित नहीं कर रहे थे, वास्तव में गोरक्षा के लिए, मानवहत्या को वैध सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। आरएसएस के आला नेता से संवाददाताओं ने जब कथित गोरक्षकों द्वारा लिचिंग की बार-बार होती घटनाओं के बारे में पूछा, जिसके लिए विपक्षी पार्टियां भाजपा के उभार को जिम्मेदार मानती हैं, इंद्रेश कुमार का जवाब था: 'देश और दुनिया के कई हिस्सों में लोग मांस खाते हैं। लेकिन, हमें यह मानना पड़ेगा कि गायों को लेकर लोग संवेदनशील हैं। इसलिए, हमें ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां कोई गाय की लिचिंग न हो और ईसान की लिचिंग न हो। हमें, विविधता में एकता का आनंद मानना चाहिए।' यानी जब तक गोरक्षी होती रहेगी, तब तक उसके जवाब में ईसानों की लिचिंग होती रहेगी। फिर यह दिला दें कि इंद्रेश कुमार ने यह बयान, कथित गोरक्षकों द्वारा माँब लिचिंग की घटनाओं में मोदी-3.0 आने के साथ आयी तेजी की पृष्ठभूमि में दिया था, आर्यन मिश्रा की हत्या जिस सिलसिले की ताज्ज्ञान नजर नहीं आती है। उल्टे स्वघोषित संघ परिवार के निर्विवाद संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के शीर्ष नेताओं से एक, इंद्रेश कुमार पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए, माँब लिचिंग की भयावह घटनाओं को यह



असौम्यद्वीन को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। इस बार माँब लिचिंग का बहाना कथित रूप से इसका शक था कि उन्होंने गोमांस खाया हो सकता है। वास्तव में माँब लिचिंग से दो-तीन रोज पहले, कथित गोरक्षकों ने इन के खिलाफ गोमांस खाने की आशंका जताते हुए शिकायत भी की थी, जिस पर पुलिस ने उनकी झोपड़ियों पर दबिश देकर, वहां मिला मांस इसका पता लगाने के लिए जांच के लिए भेज भी दिया था कि वह किस जानवर का मांस था। लेकिन, गड़बड़ी की संभावना के इस अत्यंत स्पष्ट संकेत के बावजूद, हरियाणा पुलिस ने सतर्कता के कोई कदम उठाने की जरूरत ही नहीं समझी। कथित गोरक्षकों ने इसे अपने मन की करने का संकेत माना और मांस के परीक्षण की रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाए, दोनों का जबरन अपहरण कर लिया और फिर एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर, लाठी-डंडों से कालिलाना पिटाई की। पुनः अपने संघ परिवारी नेता, इंद्रेश कुमार के ही सुर में सुर मिलते हुए, हरियाणा की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री, नायब सैनी ने एक प्रकार से गोमांस खाने के शक को, नरहत्या के लिए स्पष्ट उकसावा बताने दिया। इंद्रेश कुमार की ही तरह, भाजपायी मुख्यमंत्री ने लिचिंग की घटना को "दुर्भाग्यपूर्ण" कहा तो जरूर, लेकिन इस दरिंदगी के लिए तथाकथित गोरक्षकों की निंदा करने की उन्हीं कोई जरूरत नहीं समझी। उल्टे सैनी ने प्रकारांतर से इस मामले में अपनी पुलिस तथा प्रशासन की घोर विफलता को एक प्रकार से स्वाभाविक ही करार देते हुए कहा

कि ऐसी बातों से लोगों की भावनाएं अहत होती हैं। इसीलिए, उनकी सरकार ने गोरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया था। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और अंत में यह कि गाँवों में लोगों की भावनाएं भड़क जाएं, तो कौन रोक सकता है? दूसरी ओर, भाजपायी मुख्यमंत्री ने जोर देकर दावा किया कि चरखी-दादरी में जो हुआ, उसे माँब लिचिंग कहना ग़लत था। शायद सैनी के अनुसार, यह क्रिया की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का मामला था— गोमांस खाने के शक में हत्या! हरियाणा में लिचिंग की इन हालिया घटनाओं से और खासतौर पर चरखी-दादरी और फरीदाबाद की कथित गोरक्षकों द्वारा हत्या की घटनाएं जिस तरह, एक के फौरन बाद दूसरी हुई हैं, उनसे इसकी आशंका होना अस्वाभाविक नहीं है कि इन घटनाओं का, अगले ही महीने के आरंभ में होने जा रहे, हरियाणा के विधानसभाई चुनावों से संबंध हो सकता है। यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि हरियाणा में भाजपा को एक खासतौर पर कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में इसी राजनीतिक-सामाजिक प्रतिकूलता का पुराना नमूना कर, संघ-भाजपा जोड़ी इस तरह में भी, जहां मुस्लिम आबादी अधिक नहीं है, अपने पीछे हिंदुओं को गोबंद करने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में लगी रही है। खासतौर पर, मुस्लिम आबादी के केंद्रीयकरण की इन प्रकाशित सरकार का तख्तापलट कोई देश गोरक्षा के नाम पर खासतौर पर हिंसक गिरोहों को संगठित किया गया है, जिनकी

गतिविधियों ने मेवात के इलाके को देश की माँब लिचिंग की राजधानी ही बना दिया है। इसी सिलसिले के हिस्से के तौर पर, पिछले ही साल फरवरी में कथित गोरक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गयी थी। बाद में अगस्त के आरंभ में नूह में कथित ब्रज मंडल शोभायात्रा के नाम पर, बाकायदा दंगा भी कराया गया था, जिसका समापन भाजपा सरकार की पुलिस की पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण मुस्लिम-विरोधी कार्रवाई के साथ हुआ था। उधर गुडगांव में खुले में नमाज को रोकने के नाम पर, उकसावपूर्ण मुस्लिमविरोधी मुहिम चलायी जाती रही है। खासतौर पर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में, ध्रुवीकरण की इन कोशिशों के खास सफल न होने के बाद अब, कथित गोरक्षकों के सहरे चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दांव आजमाया जा रहा है। लेकिन, यह सब सिर्फ चुनावी चिंताओं का मामला ही नहीं है। वास्तव में आम चुनाव के नतीजे आने के बाद से, गोरक्षा के नाम पर माँब लिचिंग के मामलों में उल्लेखनीय तेजी आयी है। चुनाव नतीजों के बाद इसकी शुरूआत ख़ासतौर से हुई थी, जहां टुक ड्राइवर तथा क्लीनर समेत तीन लोगों की कथित गोरक्षकों ने पीछा कर के हत्या कर दी थी। लेकिन बाद में, जैसाकि भाजपा-शासित राज्यों में आम है, पुलिस की जांच में यह नतीजा पेश कर दिया गया और तत्परात से सरकार द्वारा उसका अनुमोदन भी कर दिया गया कि दो मरने वाले, खुद ही पुल से नदी में कूद गए थे। गोरक्षकों ने तो उनका पीछा भर किया था! उसके बाद से विभिन्न राज्यों में कथित गोरक्षकों द्वारा माँब लिचिंग की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। माँब लिचिंग की ये घटनाओं, जिनमें अक्सर दोषियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं होती है और तरह-तरह के बहानों से की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाइयों आदि से मिलकर, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से राजनीतिक-सामाजिक बदला लिए जाने का वातावरण बन रहा है। भाजपा के अनेक नेताओं के मुस्लिम-विरोधी बयान और मोदी एंड कंपनी का अपनी सोची-समझी चुप्पी से इस सब को बढ़ावा देना, इस वातावरण को और दमघोंदू बना रहा है। इंद्रेश कुमार के बयान से साफ है कि आरएसएस, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की ही कोशिश करेगा न कि टूटने देगा।

गिरिराज रचित आलोचना शास्त्र से अब बेअसर होते राहुल गांधी

राहुल गांधी फिर से अमेरिका में हैं, एक बार फिर से वे वहां बस गये भारतीयों के सामने दिल खोल रहे हैं, पुनः वे भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर बात कर रहे हैं, अब फिर से कुछ लोग, जिनका अस्तित्व इस बात पर टिका है कि उनकी पार्टी के कुकृत्यों का कहीं भी खुलासा हो-गलती से दिल्ली तक या कहीं के उल्टे से डेलाना तक- फनफना उठें; और ऐसा जवाब दें जिसके पीछे उदार विचारधारा का न तो कोई संदर्भ हो और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों का लेनामाना भी आग्रह, एक बार फिर भारत में बैठे वे लोग

नाराज होंगे जो मानते हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली है; या पहले मिली थी है तो वह 99 साल की लीज वाली थी। बहरहाल, राहुल गांधी कुछ भी कहें, इसका जवाब या स्पष्टीकरण जहां से आना चाहिये वहां से नहीं आता बल्कि उन लोगों की ओर से आता है जिन्हें न तो इसके लिये अधिकृत किया जाता है और न ही वह पार्टी का मान्यताप्राप्त बयान होता है। हिमंता बिस्वा सरमा, अनुराग ठाकुर, निशिकांत स्वते, सुमि ईरानी, कंगना रनौत या गिरिराज सिंह जैसे कुछ लोग हैं जो बार-बार एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

उनका दुर्भाग्य यही है कि वे राहुल के लिये कोई नया आलोचना शास्त्र नहीं लिख पाये हैं। वह उन्हीं मान्यताओं पर है जो 2014 के आसपास बनाया गया था और जिस हांडी पर एक बार खिड़करी पकाई जा चुकी है। यह उनके समर्थकों का भी दुर्भाग्य है कि वे उन्हीं की कही बातों पर भरोसा कर रहे हैं जबकि थोड़े बहुत जो समझदार लोग भाजपा या सरकार में हैं, वे सारे राहुल की आलोचना से किनारा कर चुके हैं। अब गिरिराज की ही बात करें तो वे पुरानी बातें ही कह रहे हैं- मसलन, 'विदेशी धरती पर भारत की आलोचना', 'भारत की

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस उत्साहित



हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में कौन विजयी होगा? क्या सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में अपना कब्जा बरकरार रखेगी या फिर कांग्रेस जीत का मौका भुनावेगी? देश की निगाहें महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में आसन चुनावों के नतीजों पर थी टिकी हैं, जो इन राज्यों के भविष्य को आकार देंगे और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे हरियाणा 90 सीटों के साथ एक विविधतापूर्ण बहुकोणीय मुक़ाबले के लिए तैयार है। मुख्य मुक़ाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। फिर भी, आप, समाजवादी पार्टी, सीपीआई (एम), सीपीआई और हरियाणा लोकहित पार्टी जैसे पार्टियां भी मैदान में हैं, जो चुनावी गतिशीलता में विविधता ला रही हैं। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने दुबुधत चौटाला को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। वहीं, इनेलो और बसपा ने अभय सिंह चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं। भाजपा की ओर से नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी समस्याएं हैं। भाजपा के मामले में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी। अन्य प्रमुख हस्तियों और जिला नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा दे दिया। गठबंधन सहयोगी आप के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा के दौरान हुड्डा समेत हरियाणा के कांग्रेस नेता कुछ ही सीटें देने को तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस दस साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी को लेकर आशावादी है। पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी को गठबंधन के लिए रणनीतिक रूप से लुप्तवदी की कोशिश कर रही है। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप में अभी भी जेल में हैं। हरियाणा चुनाव अहम हैं। भाजपा तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है, जबकि कांग्रेस सत्ता हासिल करना चाहती है। अन्य क्षेत्रीय दल भी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए होड़ में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी दस सीटें जीती थीं। 2024 में उसे केवल पांच सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस ने बाकी पांच सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से वंचित भाजपा ने जद(यू) और तेलुगु देशम की मदद

से सरकार बनाई। 2014 से पहले हरियाणा में भाजपा एक छोटी खिलाड़ी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पार्टी ने गति पकड़ी। 2019 में भाजपा ने 40 सीटों के साथ सरकार बनायी, जो बहुमत से सिर्फ छह कम थी, दुबुधत चौटाला की जनानावक जनता पार्टी (जेजेपी) ने दस सीटें जीतकर भाजपा का समर्थन किया। हालांकि, जेजेपी ने हाल ही में भाजपा के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर लिया है। हरियाणा में, भाजपा का वोट शेयर 2019 में 58.2 प्रतिशत से घटकर 2024 में 46.1 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण किसानों द्वारा कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी की मांग करना था। 2024 में, क्षेत्रीय नेताओं और कांग्रेस के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भाजपा के वोट शेयर को पीछे छोड़ दिया। मार्च में, भाजपा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। नये मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने का वायदा किया है और जाट का साथ देना का लक्ष्य रखा है। हालांकि, भाजपा को जाटों का समर्थन नहीं है। साथ ही, सैनी के छह महीने के छोटे कार्यकाल ने उनके प्रभाव को सीमित कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी लोकसभा सीटों को दोगुना करने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस

बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, किसानों के मुद्दों और विवादस्पद अग्निवीर योजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी जनता के सुझावों के आधार पर अपना घोषणापत्र तैयार कर रही है, जिसमें बूटों के लिए 6,000 रुपये पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। पार्टी को पहले बार मतदान करने वाले 452,000 मतदाताओं और 40 लाख युवा मतदाताओं पर भी भरोसा है। कांग्रेस का लक्ष्य विपक्षी वोटों को एकजुट करना है, जबकि भाजपा उन्हें रणनीतिक रूप से विभाजित करना चाहती है। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में आप का कुछ प्रभाव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा संकेतों के मुताबिक आप ने पांच सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। कांग्रेस में भी खटपट चल रही है। कांग्रेस गुटबाजी का सामना कर रही है। यह हुड्डा और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में दो समूहों में विभाजित है। पार्टी दोनों गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुड्डा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिका के कारण अधिक प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में दलबदल और पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदार शामिल हैं। हरियाणा में भाजपा को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। भाजपा की कमजोरियां हैं राज्य स्तर पर मजबूत नेतृत्व की कमी और विपक्ष के आरोपों के जवाब में किसी दमदार बात का न होना। पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभी तक किसी भी चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया है। कांग्रेस को आत्मसंतुष्टि, आंतरिक संघर्षों को दूर करके संगठन को मजबूत करना चाहिए। उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद भाजपा को विद्रोह का सामना करना पड़ा और कुछ प्रभावशाली नेताओं ने पार्टी के लिए अपनी रणनीति बदली। रंजीत जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। टिकट के लिए बहुत सारे दावेदार पार्टी की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। अंततः, अंकगणित ही कांग्रेस की जीत तय करेगा। साथ ही, इंडिया गठबंधन की एकता भी जरूरी है। अगर किस्मत अच्छी रही तो भाजपा सम्मानजनक संख्या में सीटें हासिल करके नुकसान को कम कर सकती है, जिससे एक मजबूत विपक्ष बन सकता है। कांग्रेस को गलतियों से बचना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अन्यथा, वह एक सुनहरा अवसर खो देगी।

सुपर टाइफून यागी तूफान का कहर

वियतनाम में मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंची

वियतनाम में टाइफून यागी और उसके बाद भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या गुरुवार को लगभग 200 हो गई, जबकि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विनाशकारी तूफान के बाद 125 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। वियतनाम के वीएनएक्सप्रेस अखबार ने बताया कि अब तक 197 लोग मारे गए हैं और 800 से अधिक घायल हुए हैं जबकि 128 अन्य लापता हैं। राजधानी



हनोंई में, रेड नदी से बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है लेकिन कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। लोग ताई हो जिले की एक सड़क पर जाने के लिए अपने घुटनों से ऊपर गढ़े भूरे पानी से होकर गुजरें और व्यापक विनाश के दृश्यों के बीच कुछ लोग छोटी नावों में सड़क पर चल रहे थे। हनोंई में बाढ़ कथित

तौर पर दो दशकों में सबसे भीषण बाढ़ है, और इसके कारण बड़े पैमाने पर निकासी हुई है। सप्ताह की शुरूआत में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई जब मंगलवार को उत्तरी वियतनाम के लाओ काई प्रांत में लैंग नु की पूरी बस्ती अचानक बाढ़ में बह गई। जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए सैकड़ों बचाव कर्मियों ने बुधवार को अथक प्रयास किया, लेकिन गुरुवार सुबह तक 53 ग्रामीण लापता थे, जबकि सात और शव मिले, जिससे वहां मरने वालों की संख्या 42 हो गई।

खास खबर

अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया तिर-बितर

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तिर-बितर कर दिया है। यह जानकारी स्मृतिक ने दी। हजारों लोगों ने कांग्रेस भवन के नजदीक सिटी सेंटर में बुधवार को एक्टर होकर पैशन बढ़ाने के कानून पर राष्ट्रपति के वीटो का विरोध किया। पुलिस ने उन रिपोर्टों के बाद लोगों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के वीटो को रोक पाने में नाकाम रहने की रिपोर्टों के आने के बाद शुरू हुआ। इसी मोटर पीछे से प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलीयाँ और आंसू गैस का उपयोग किया गया।

खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती
बाका। बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री एवं बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को गुरुवार तड़के बाका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्टों से यह जानकारी मिली। बाका ट्रिब्यून ने मेडिकल बोर्ड के निर्णय का हवाला देते हुये बताया कि मेडम (खालिदा) को एक्विकेयर अस्पताल ले जाया गया जहां उनके चिकित्सक प्रोफेसर एजेडएम जाहिद हुसैन ने उनके कई शारीरिक परीक्षणों के लिये कहा है। बीएनपी मीडिया सेल के सैरुल कबीर खान ने कहा कि सुश्री जिया अपने गुरुशान घर से लगभग 1.40 बजे अस्पताल पहुंचीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले 21 अगस्त को सुश्री जिया 45 दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 जून को विशेषज्ञ सर्जनों की एक टीम ने उनकी छाती में पेरामेकर लगाया।

बंगलादेश के पूर्व सांसद भारत भागते समय सीमा पर गिरफ्तार
बाका। बंगलादेश के बाईर गाई बंगलादेश (बीजीबी) ने रावजान (चटगांव-6) के पूर्व सांसद ए बी एम फजले करीम चौधरी को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। स्थानीय अखबार बाका ट्रिब्यून ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अखबार की रिपोर्टों के अनुसार, बीजीबी के जनसंघर्ष अधिकारी शरीफुल इस्लाम ने पुष्टि की है कि श्री चौधरी को अखंडा, ब्राह्मणबर्निया के पास सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि देश में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के कारण पांच अगस्त को अत्यामी लीग सरकार के पतन के बाद से पूर्व सांसद कथित रूप से छिपे हुए थे।

अनुष्का सेन बनीं सियोल

साउथ कोरिया के बिलबोर्ड पर फीचर होने वाली पहली इंडियन स्टार

मुंबई, एजेंसी।

अभिनेत्री अनुष्का सेन सियोल, साउथ कोरिया के बिलबोर्ड पर फीचर होने वाली पहली इंडियन स्टार बन गयी हैं। ग्लोबल स्टार

अनुष्का सेन के दुनिया भर में बहुत सारे फैंस हैं। भारत में दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी उनके आर्ट को खूब सराहा जाता है। ऐसे में भारत में सबका दिल जीतने वाली अनुष्का हाल ही में अपने एक सफल डिजिटल रिलीज के बाद, 22 साल की कम उम्र में बड़ी उपलब्धि अपने नाम करते हुए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रही हैं। अनुष्का सेन की सोल, कोरिया में यात्रा के पहले दिन ही उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। म्यो-डॉंग, सोल की अपनी पसंदीदा शॉपिंग स्ट्रीट पर उनके पोस्टर्स कई बिलबोर्ड्स पर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, शहर के अन्य हिस्सों में भी उनके पोस्टर्स दिखे। यह किसी भी भारतीय स्टार के लिए दक्षिण कोरिया में बिलबोर्ड्स पर दिखने का पहला मौका था! अनुष्का सेन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके पोस्टर्स कोरिया की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह उनके फैंस के लिए एक अर्थ का पल है! यह किसी भी भारतीय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्हें एक नए क्षेत्र में पहचान मिली है। अनुष्का सेन ने न सिर्फ भारत में बल्कि दक्षिण कोरिया में भी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया है। ऐसे में इस दौरान, उनके फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ पड़े, लोगों का रीस्पॉन्स बताता है कि अनुष्का ने हम सभी को गर्व से भर दिया है। श्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी सेलिब्रिटीज ने वेस्ट में अपना नाम कमाया है, लेकिन अनुष्का एक अलग ग्लोबल स्टार के रूप में उभरी हैं, जो ईस्ट में अपना नाम कमा रही हैं। अनुष्का सेन को ली जंग-सब द्वारा डायरेक्टड एंथिथिसस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट 'एशिया' में फीचर किया जाएगा। वह दुनिया भर के एक्टर्स के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फिल्म में, वह पहली बार एक हिटवुमन की भूमिका निभाएंगी और पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं। अनुष्का सेन ने अपने अभिनय करियर में एक नया मुकाम हासिल किया है, और वह अपनी इस नई भूमिका से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं! अनुष्का सेन कोरिया में बहुत पॉपुलर हो रही हैं और उन्हें कोरियाई सरकार के एक संपटन कोरिया ट्रेड अगिनाइजेशन ने टूरिज्म का ब्रांड अम्बेसडर बनाया था, जो यह दिखाता है कि वो एक ग्लोबल स्टार हैं। उन्होंने भारत के लिए ईस्ट में एक नया रास्ता खोल दिया है, जहां पहले से ही दुनिया भर के युवा आकर्षित हो रहे हैं। अनुष्का सेन ने भारत को ग्लोबल लेवल पर रिजेंट करने का एक नया मौका दिया है और उनकी पॉपुलैरिटी कोरिया में भारत के लिए एक नई शुरूआत है! अनुष्का न सिर्फ एक नए क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं, बल्कि एक ग्लोबल स्टार बन गई हैं, जो शोहरत की परिभाषा को बदल रही है। ग्लोबल स्ट्रेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुष्का सेन पहली स्टार हैं जो कोरियन ड्रैम को भारत में ला रही हैं, जिसपर हमें गर्व हो रहा है! इस तरह से वह एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई हैं और दिखा रही हैं कि इंडियन टेलेंट ग्लोबल लेवल पर पहचान पा सकता है।



घर लेने वालों को मिल सकती है कंटों में राहत



रियल

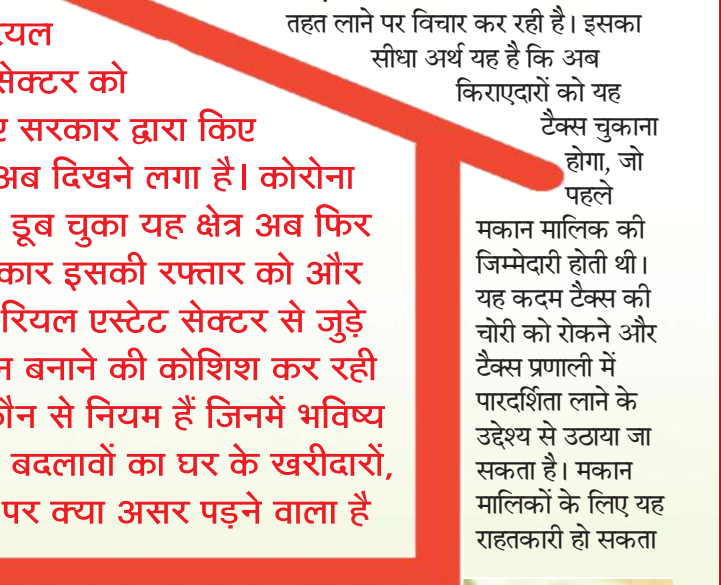
एस्टेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जीएसटी के नियम इस पर गहरा असर डालते हैं। नौ सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई अहम बदलावों की किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रियल एस्टेट क्षेत्र महामारी के बाद फिर से गति पकड़ रहा है और कराधान संबंधी कोई भी बदलाव इसका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं।

कौन से बदलाव संभव
जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिनका प्रभाव इस क्षेत्र के भविष्य पर पड़ेगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से जुड़ी टैक्स की अस्पष्टताओं को दूर करने, जमीन की कीमत को कुल कीमत से अलग कर कराधान करों और वाणिज्यिक संपत्तियों पर रिवर्स चार्ज लागू करने जैसे फैसले रियल एस्टेट क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। इन बदलावों से जहां खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किराएदारों के लिए कुछ नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय किस तरह से रियल एस्टेट क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और क्या बदलाव सामने आते हैं।

रूप से कमी ला सकता है और खरीदारों को लाभ पहुंचा सकता है। यदि जमीन की कीमत पर जीएसटी की गणना नहीं की जाती, तो घर खरीदने की लागत कम हो सकती है, जिससे यह कदम रियल एस्टेट बाजार को गति दे सकता है।

किराएदारों पर बढ़ सकता है बोझ
जीएसटी काउंसिल संभवतः वाणिज्यिक संपत्तियों के किराए पर 18% जीएसटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाने पर विचार कर रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब किराएदारों को यह टैक्स चुकाना होगा, जो पहले मकान मालिक की जिम्मेदारी होती थी। यह कदम टैक्स की चोरी को रोकने और टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है। मकान मालिकों के लिए यह राहतकारी हो सकता है।

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का असर अब दिखने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग डूब चुका यह क्षेत्र अब फिर रफ्तार पकड़ रहा है। सरकार इसकी रफ्तार को और ज्यादा तेज करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कराधान नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं कि वे कौन से नियम हैं जिनमें भविष्य में बदलाव संभव है और इन बदलावों का घर के खरीदारों, किराएदारों और डेवलपर्स पर क्या असर पड़ने वाला है।



दिलचस्प होगा कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय किस तरह से रियल एस्टेट क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और क्या बदलाव सामने आते हैं।

कंप्लीशन सर्टिफिकेट
कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र में जीएसटी के अंतर्गत कई अस्पष्टताएं रही हैं। काउंसिल इस बार प्रोफेशनल लोकेशन चार्ज और निर्माण सेवाओं (कंस्ट्रक्शन सर्विस) को समग्र आपूर्ति में शामिल करने पर स्पष्टता दे सकती है। इसका उद्देश्य यह होगा कि कर की गणना मुश्किल सेवा, यानी निर्माण सेवाओं का आधार पर की जा सकेगी। इस बदलाव से टैक्स गणना की प्रक्रिया डेवलपर्स और खरीदार दोनों के लिए अधिक सरल हो जाएगी, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इससे टैक्स चोरी पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, जो वर्तमान में एक बड़ी चिंता का विषय है।

...तो प्रापर्टी प्राइस में जमीन के दाम घटाकर लगेगा कर
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक और प्रमुख मुद्दा जमीन की कीमत पर कराधान है। फिलहाल, प्रापर्टी की कुल कीमत पर जीएसटी लागू होता है, जिसमें जमीन की लागत भी शामिल होती है। काउंसिल अब यह प्रस्तावित कर सकती है कि जमीन की कीमत को कुल बिक्री मूल्य से घटाया जाए और केवल निर्माण सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाए। यह बदलाव प्रापर्टी की कीमतों में संभावित

है, जबकि किराएदारों के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय भार बन सकता है।
संपत्ति क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार
अगर इन नियमों पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकारात्मक निर्णय आया तो रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा जिसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। इसके अलावा जब घर की कीमत में से जमीन के दाम घटाने के बाद कराधान किया जाएगा तो घर खरीदने वालों को कुछ सस्ता घर मिलने का रास्ता भी साफ होगा। साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में स्पष्टता आने से इस पर टैक्स की गणना बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए ही आसान हो जाएगी।

पेज 1 का शेष

हर 4 माह में बदलेंगे जिलों...
सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। स्वच्छता का यह अभियान जन आन्दोलन बने, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में मंत्रिण प्रत्येक माह में कम से कम एक बार 24 घण्टे के लिए अपने प्रभार के जनपद में प्रवास करेंगे। शासन से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभारी मंत्री कोर कमेट्री से चर्चा करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रत्येक माह शासन के सम्बन्धित विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद के सम्मानित प्रवृद्ध नागरिक, धर्माचार्यों, प्रगतिशील किसानों, व्यापारिक संगठनों सहित सामाजिक नेताओं के समूहों में से किसी एक के साथ प्रत्येक स्थलों, ग्राम सचिवालय, क्रय केन्द्र, फेयर प्राइस शॉप, कृषि विज्ञान केन्द्र में से किसी एक का भौतिक निरीक्षण प्रवास के दौरान करना अपेक्षित है। अदल आवासीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों, निमाणधीन कस्तूरबा गांधी विद्यालय, विश्वविद्यालयों, संचालित विद्यालयों के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं पॉलीटेक्निक/आईटीओ आइओ के महाविद्यालयों की भी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्थानीय पर्यटन विकास की सम्भावनाओं की तलाश कर उनके प्रचार-प्रसार पर चर्चा होनी चाहिए। जनपद में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर उद्यमी मित्रों और स्थानीय बैंकर्स के साथ चर्चा की जाए। जनपद में जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के साथ यातायात समस्या के सम्बन्ध में बैठक की जाए। जनपद में सड़क सुरक्षा के उपायों की समीक्षा करें। जनपद की समीक्षा बैठक में आकांक्षामक विकास खण्डों की समीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए। आयुष्मान कार्ड, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सालयों में चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, आगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सचिवालयों के निर्माण एवं गाँव में तैनात कार्मिकों की उपस्थिति आदि का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
केजरीवाल को जेल या बेल!....
से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी मुख्यमंत्री केजरीवाल को विशेष अदालत की अनुमति के बाद 25 जून को पूछताछ और फिर 26 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मुकदमे में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। यदि सीबीआई की ओर से जून में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया होता तो वह जेल से रिहा कर दिए जाते। शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं के आरोप के आधार पर केजरीवाल जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था। शुरू में मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम आरोपियों में नहीं था। सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान केजरीवाल जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि अधिनस्थ अदालत को प्रतिकार करने की अनुमति केवल आधाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इस पर श्री केजरीवाल पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी ने दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत आरोपी को नॉटिस जारी करने के संबंध में वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारों पर हिरासत के दौरान बहस की गई थी। इसके बाद विशेष अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। इसलिए याचिकाकर्ता को फिर से उसी मुद्दे पर वहां बहस करने के लिए वापस भेजना न्यायोचित नहीं होगा। पीठ के समक्ष गुरुवार पांच सितंबर 2024 को श्री सिंघवी ने कहा, शायद यह एकमात्र ऐसा मामला है, जिसमें मुझे

(केजरीवाल) इस अदालत से सख्त धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दो रिहाई आदेश मिले। उच्च न्यायालय से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई द्वारा पहले से तय गिरफ्तारी हुद्दों शीर्ष अदालत को श्री सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम 2022 में दर्ज मुकदमे में नहीं था और उन्हें इस साल 2024 जून में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, रती अदालती आदेश मेरे पक्ष में हैं। यह एक पहले से तय की गई गिरफ्तारी है, ताकि उन्हें (मुख्यमंत्री) जेल में रखा जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखते हुए आगे कहा, रसवृत्तों के साथ छेड़छाड़ का कोई सबाल ही नहीं है, क्योंकि लाखां दस्तावेज हैं, जिनमें से कई तो डिजिटल हैं। उनके मुक्किल न्यायिक हिरासत में रहते हुए गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और इस मामले में पांच आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं।
भड़के योगी के....
घटना, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन में रही है। जिसके यहां अपराध हुआ उस ज्वेलर्स के समर्थन समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से एक भी शब्द नहीं निकले। समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ है, सपा उसकी बजाय अपराधियों के साथ खड़ी नजर आनी। सुल्तानपुर घटना में बाँधल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी के एनकाउंटर पर अब समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर उसके समर्थन में जुट गई है। हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होता। हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। घटना में बाँधलों के घर से लूट का 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी की जब-जब सरकार रही है, अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करती रहती है। सपा राज में राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर घुमाया था। जीप को ले जाकर एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिया गया था। आज तक उस घटना में कितनों की सजा हुई। यह समाजवादी पार्टी जानती है। बदमाँ और मथुरा के घबहार बाग कांड को कौन भूल सकता है। इसमें पुलिस अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुजफ्फरनगर में हमारी एक बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मुजफ्फरनगर देगे में कितने निर्दोष मारे गए थे, समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए।

मठधीश-माफिया में फर्क.....
में तमाम एनकाउण्टरों पर उंगली उठी है। नोएडा में एक जिम इन्स्ट्रक्टर का झूठा एनकाउण्टर हुआ था तब भी हम लोगों ने मामला उठाया था कि पुलिस वालों ने लूट के लिए एनकाउण्टर किया है उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक प्रदेश में जितने भी झूठे एनकाउण्टर के नाम पर हत्याएं हुई हैं। उसमें सबसे ज्यादा पीडीए परिवार की हुई है। सरकार एनकाउण्टर से लोगों को डराना चाहती है। बदनाम करने के लिए जानबूझ कर दूँ-दूँकर एनकाउण्टर किया जा रहा है। अधिकारी रात भर एनकाउण्टर की रणनीति बनाते हैं और यह भी रणनीति बनाते हैं कि हत्या करने पर वे कैसे बच सकते हैं। जब इस तरह के अधिकारी हैं तो उनसे कैसे न्याय मिलेगा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम जनता को न्याय दिलाने के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष करेंगे। इसके लिए भी जैसा भी संघर्ष करना पड़ेगा समाजवादी लोग पीछे नहीं रहेंगे।
अयोध्या में चल रही है जमीन की....
दामों में जमीनें ले लीं मगर समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ है। श्री यादव ने कहा कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं। अयोध्या एक वर्कड क्लास सिटी बने, इसके लिए वह हर सहयोग को तैयार है मगर विकास के लिये दिमाग का होना जरूरी है जो भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। दो साल बाद जब समाजवादी सरकार आणी तो न सिर्फ अयोध्या को विश्वस्तरीय पर्यटन नगरी बनायेगे बल्कि गरीबों को सर्किल रे ट्रे बढाकर मुआवजा दिया जाएगा। सुल्तानपुर की घटना का जिम्मेदार कर्ते हुये उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं कर रही हैं। मीश यादव एनकाउंटर केस में गांव वाले भी कहते हैं कि पुलिस रात में उठाकर ले गयी, उसके पास से जो मोटरसाइकिल मिली उसकी चोरी की रिपोर्ट घटना में कई दिन बाद लिखी गयी। मीश यादव के पास नया बैग मिला, उस बैग में नए कपड़े मिले। दरअसल यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या थी और यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले तमाम एनकाउंटर हुए जिनमें सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग मारे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुये कहा कि जिसका दिल दिमाग नाकारात्मक हो उससे विकास की क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर दिमाग होता तो पुलिस चण्पल में एनकाउंटर न करती। ये सरकार लूट के साथ डर दिखाकर एनकाउंटर कर रही है। जो अधिकारी रात में हत्या की रणनीति बनाएँ, उनसे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है।